एस.एस. संधावलिया और बी.एस.यादव, जे. के समक्ष

जयदेव सिंह और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1981 की सिविल रिट याचिका संख्या 5153।

" 22 दिसंबर, 1981।

मोटर वाहन अधिनियम (1939 का IV)—धारा 54, 515, 56 57, 60| और 63(11)-अधिनियम के तहत परमिट देने का आदेश-की प्रकृति-क्या अर्ध-न्यायिक-धारा 57-अनुदान प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद स्वीकृत राष्ट्रीय परमिट-

क्या योग्यता के आधार पर आदेश की समीक्षा करने की दृष्टि से अनुदान प्राप्तकर्ताओं को अपने परमिट जमा करने के लिए कहा जा सकता है।

माना गया कि मोटर, वाहन अधिनियम, 1939 के तहत परमिट जारी करने वाले ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही चरित्र में अर्ध-न्यायिक है।

(पैरा 10).

माना गया कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो राज्य परिवहन आयुक्त या इसी तरह के प्राधिकार को अधिनियम के तहत परमिट मंजूर करने वाले अर्ध-न्यायिक निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार दे सके और न ही किसी न्यायिक या 'अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण' में कोई अंतर्निहित शक्ति या अधिकार क्षेत्र है कि वह किसी निर्णय किए गए मामले को फिर से खोल सके और केवल गुण-दोष के आधार पर निर्णय में परिवर्तन करके मामले को सही कर सके। इसलिए, जिन व्यक्तियों के पक्ष में परमिट दिए गए हैं, उन्हें मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को योग्यता के आधार पर आदेश की समीक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें जमा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। (पैरा 10),

भारत के संविधान के अनुच्छेद एस26/227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि निम्नलिखित प्रभाव के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जा सकता है: -

V) मामले के रिकॉर्ड तलब किए जा सकते हैं;

(11) उन्होंने याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए नोटिसों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी;

(जैसे) कि प्रतिवादियों को 16 नवंबर, 1981 को उनके पास राष्ट्रीय परमिट जमा करने के संबंध में आदेश को लागू करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की जाए।

{iv) विवादित नोटिसों के संचालन पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया जा सकता है;

(यू) प्रस्ताव के नोटिस जारी करने और प्रमाणित प्रतियों के उत्पादन से छूट।

जे.के. सिब्बल के वरिष्ठ वकील एच. एल. सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं को संबोधित किया।

प्रतिवादी की ओर से हरभगवान सिंह, महाधिवक्ता, हरियाणा और जी.एल. बाटा, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता।

निर्णय

बी.एस.यादव, जे.

(1) यह निर्णय 1981 के सी.डब्ल्यू. संख्या 5153, 5152, 5300, 5214, 5275, 5304, 5219, 5154, 5311 और 5233 का निपटान करेगा क्योंकि इन सभी मामलों में कानून का सामान्य प्रश्न शामिल है। पक्षों के वकील इस बात पर सहमत हैं कि 1981 के सी.डब्ल्यू. 5153 में निर्णय इन सभी मामलों को कवर करेगा, इसलिए मैं केवल उस मामले के तथ्य दूंगा।

(2) भारत सरकार ने पात्र व्यक्तियों को दिए जाने के लिए हरियाणा राज्य को एक निश्चित संख्या में राष्ट्रीय परमिट आवंटित किए थे। उस संख्या में से हरियाणा राज्य ने कुछ अंबाला क्षेत्र को और कुछ हिसार और फरीदाबाद क्षेत्रों को ऐसे व्यक्तियों को देने के लिए आवंटित किया। इस मामले में हमारा संबंध अंबाला क्षेत्र से है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, अंबाला ने आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किए और उन्हें स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। कुछ आवेदन प्राप्त हुए थे. उन आवेदनों का सार बाद में समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया और उन आवेदनों के खिलाफ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए राज्य परिवहन आयुक्त, हरियाणा के कार्यालय में प्रदर्शित किया गया। चूंकि निर्धारित अवधि के भीतर सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ था, आवेदकों को 23 जून, 1979 और 19 जुलाई, 1980 को बुलाया गया था। सार्वजनिक वाहक ऑपरेटरों के रूप में उनकी प्रामाणिकता का पता लगाना और प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच करना। ■ राष्ट्रीय परमिट देने के उनके दावों का मूल्यांकन किया गया। सभी मामलों की जांच के बाद, उक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश अनुलग्नक पी. 1 में उल्लिखित 12 व्यक्तियों (वर्तमान याचिकाकर्ताओं सहित) को राज्य टार्नस्पोर्ट आयुक्त द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर राष्ट्रीय परमिट दिए गए थे।

(3) 2 नवंबर, 1981 को राज्य परिवहन आयुक्त ने वर्तमान रिट याचिकाकर्ताओं और अन्य को अलग-अलग नोटिस जारी कर उन्हें अपने परमिट सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, अंबाला के पास तुरंत, लेकिन 16 नवंबर, 1981 से पहले जमा करने का निर्देश दिया। आगे आदेश दिया गया कि यदि उन्हें उक्त परमिट जमा करने पर कोई आपत्ति है, तो वे 9 नवंबर, 1981 को उनके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। वह आदेश निम्नलिखित कारणों से पारित किया गया था: -

“और जबकि इन परमिटों के अनुदान के संबंध में कुछ रिट याचिकाएं दायर की गई थीं और राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा पारित आदेशों को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी, जिसमें

याचिकाकर्ताओं के पास अच्छा, यदि जिन लोगों को परमिट दिए/जारी किए गए हैं उन पर दावा करना बेहतर नहीं है।

उपरोक्त मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर, परमिट देने के पूरे मामले पर नए सिरे से विचार करना अनिवार्य हो गया है।

(4) उक्त परिवहन आयुक्त के समक्ष आपत्तियां दायर की गईं, - अनुबंध पी 3 के माध्यम से। आपत्तियों को सुनने के बाद, - 13 नवंबर, 1981 के आदेश में कहा गया कि परिवहन आयुक्त ने उन्हें खारिज कर दिया और आदेश दिया गया कि यदि अनुदान के लिए जारी किए गए नोटिस के संदर्भ में 16 नवंबर, 1981 तक परमिट जमा नहीं किए गए, तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अंबाला उन परमिटों को जमा करने के लिए कदम उठाएगा और उन परमिटों के खिलाफ आगे के संचालन को तब तक रोक देगा। पूरे मामले पर नये सिरे से निर्णय लिया गया. प्रदर्श आर. 1 उस आदेश की प्रति है। *

(5) वर्तमान याचिका नोटिस अनुलग्नक पी 2 जारी होने के बाद दायर की गई थी। याचिकाकर्ता उक्त नोटिस को चुनौती दे रहे हैं और उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ अनुरोध किया है कि नोटिस अनुबंध पी. 2 परमिट देने के संबंध में पहले पारित आदेश की समीक्षा के समान है।

विभिन्न आवेदकों की प्रामाणिकता का पता लगाना और उनकी उपयुक्तता का आकलन करना और इस प्रकार वह आदेश अर्ध-न्यायिक प्रकृति का है और इसलिए, राज्य परिवहन नियंत्रक अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता है।

(6) हरियाणा राज्य (प्रतिवादी संख्या 1) और राज्य परिवहन आयुक्त, हरियाणा, (प्रतिवादी संख्या 3) ने इस याचिका का विरोध किया है और जवाब दाखिल किया है। उनके द्वारा यह दलील दी गई थी कि राष्ट्रीय परमिट देने के संबंध में कुछ याचिकाएँ भरी गई थीं और जब वे रिट याचिकाएँ इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आईं तो सरकार ने पूरे मामले की नए सिरे से जाँच करने की पेशकश की ताकि उन याचिकाकर्ताओं और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों के मन से किसी भी वास्तविक संदेह को दूर करें और उसके बाद उन रिट याचिकाओं को हमने खारिज कर दिया। उन आदेशों के मद्देनजर, परमिट देने के लिए पूरे मामले पर नए सिरे से विचार करना जरूरी हो गया था और इसलिए, जिन व्यक्तियों को परमिट दिए गए थे, उन्हें सुविधा के लिए संबंधित सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के पास जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इस न्यायालय में दिए गए आश्वासन के अनुपालन में पूरे मामले पर पुनर्विचार करने का मामला। यह भी दलील दी गई है कि परमिट जमा करने के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विधिवत सुनवाई की गई और उसके बाद आदेश (जिसकी प्रति प्रदर्शनी आर. 1 है) पारित किया गया।

(7) प्रारंभ में विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा ने दो प्रारंभिक आपत्तियाँ उठाईं। पहला यह था कि जिन याचिकाकर्ताओं की रिट में सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी, उन्हें वर्तमान याचिका में पक्षकार बनाया जाना चाहिए था क्योंकि उनके अधिकार प्रभावित होंगे। दूसरा यह था कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं को पिछले आदेशों के खिलाफ अपील दायर करनी चाहिए थी।

(8) विद्वान महाधिवक्ता की उपरोक्त प्रारंभिक आपत्तियों की सराहना करने के लिए, कुछ और तथ्य देना आवश्यक है, जनित व्यक्तियों को फरीदाबा क्षेत्र में राष्ट्रीय परमिट नहीं दिए गए थे। उन्होंने इस न्यायालय में 1981 की सिविल रिट याचिका संख्या 4133 और अन्य रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के साथ-साथ संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम हरियाणा राज्य को प्रस्ताव की सूचना के बाद उन्होंने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“विद्वान महाधिवक्ता, हरियाणा, इस प्रकार बताते हैं;-

"आपत्तियों को पूरा करने के लिए, सरकार ने इन परमिटों को देने के लिए पूरे राज्य के लिए निर्धारित समय के भीतर दायर किए गए सभी आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने का निर्णय लिया है, जिनमें वे आवेदन भी शामिल हैं जिन्हें परमिट दिया गया है।" इसे देखते हुए, याचिकाकर्ता के वकील इस याचिका पर जोर नहीं देते हैं। खारिज कर दिया गया।”

विद्वान महाधिवक्ता की पहली प्रारंभिक आपत्ति में कोई दम नजर नहीं आता। 1981 की सिविल रिट संख्या 4133 फ़रीदाबाद क्षेत्र में राष्ट्रीय परमिट न देने से संबंधित है। यह पक्षकारों के बीच स्वीकृत तथ्य है कि अमहला या हिसार क्षेत्र के किसी भी आवेदक ने उसे राष्ट्रीय परमिट न दिए जाने के बारे में इस न्यायालय में कोई रिट दायर नहीं की थी। वर्तमान याचिकाकर्ता उस रिट के पक्षकार नहीं थे। इसलिए, हम इस बात की सराहना करने में विफल रहते हैं कि कैसे 1981 के सी.डब्ल्यू. 4133 के याचिकाकर्ता और अन्य संबंधित मामले वर्तमान रिट के लिए आवश्यक पक्ष हैं। यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि उत्तरदाताओं द्वारा अपने उत्तर में इस आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया है।

(9) अपनी दूसरी प्रारंभिक आपत्ति को विस्तृत करने के लिए विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि 1981 की सिविल रिट संख्या 4133 में आदेश न्यायिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद पारित किया गया था यानी राज्य को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था और इसलिए, उस रिट में पारित आदेश को वर्तमान रिट में चुनौती नहीं दी जा सकती और इसे अपील में चुनौती दी जानी चाहिए थी। इस आपत्ति में भी कोई दम नजर नहीं आता 1981 की रिट संख्या 4133 में, इस न्यायालय द्वारा पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। तत्कालीन विद्वान महाधिवक्ता ने एक बयान दिया और उस बयान के आधार पर रिट याचिकाकर्ता ने वह रिट वापस ले ली। यह पार्टियों के बीच हुआ एक प्रकार का समझौता था। यदि 'पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर समझौता किया होता, तब भी स्थिति ऐसी ही होती।' इसके अलावा, वर्तमान रिट में याचिकाकर्ता उस रिट में पारित आदेश की वैधता या औचित्य को चुनौती नहीं दे रहे हैं। उनकी एकमात्र शिकायत यह है कि 'राज्य सरकार या राज्य परिवहन आयुक्त उन्हें पहले से दिए गए परमिट जमा करने के लिए नहीं कह सकते हैं और इसके अलावा उन्हें परमिट देने के आदेश की समीक्षा नहीं की जा सकती है।'

(10) अब, हम मामले के गुण-दोष पर आते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 47 से 59-ए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली

प्रक्रिया से संबंधित है। स्टेज कैरिज परमिट या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट या निजी वाहक परमिट के अनुदान के लिए आवेदन पर विचार करने में, और उन परमिटों की अवधि और नवीनीकरण और उन शर्तों के बारे में जो परमिट से जुड़ी हो सकती हैं। धारा 60 परमिट को रद्द करने और निलंबित करने से संबंधित है। माना कि मौजूदा मामले में अधिनियम की धारा 60 के तहत कार्रवाई नहीं की जा रही है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान अधिनियम की धारा 63 के प्रावधान की ओर आकर्षित किया है। उस धारा की उपधारा 11 इस प्रकार है:-

“63(11). उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन उपधारा (15) के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, उपयुक्त प्राधिकारी, लंबी दूरी के अंतरराज्यीय सड़क परिवहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, किसी राज्य में मोटर वाहनों के मालिकों को राष्ट्रीय परमिट प्रदान करना, जो माल की ढुलाई के लिए ऐसे वाहनों का उपयोग करते हैं, या उपयोग करने का इरादा रखते हैं, किराया या इनाम के संबंध में। मोटर वाहनों की इतनी संख्या जितनी केंद्र सरकार उस राज्य के संबंध में अपनी ओर से निर्दिष्ट कर सकती है और धारा 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50-ए, 60, 61 और 64 के प्रावधान, जहां तक हो जैसा हो सकता है, राष्ट्रीय परमिट के अनुदान के लिए या उसके संबंध में आवेदन करें;

बशर्ते कि किसी राज्य के लिए निर्दिष्ट राष्ट्रीय परमिटों की संख्या को संबंधित राज्य सरकार से परामर्श के बाद ही बदला या संशोधित नहीं किया जाएगा। अधिनियम की धारा 63 की उप-धारा 12 और 13 बताती है कि किसे राष्ट्रीय परमिट जारी किए जाने हैं और कितनी संख्या तक। उप¬

धारा 15 केंद्र सरकार को उप-धारा 11 के संबंध में नियम बनाने की शक्ति देती है। वर्तमान मामले में यह विवाद में नहीं है कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं को अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद राष्ट्रीय परमिट दिए गए थे। सीखा याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रीय परमिट प्रदान करते समय अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं और इसलिए, उन्हें याचिकाकर्ताओं से उनकी समीक्षा के उद्देश्य से परमिट जमा करने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कि परमिट देने वाला प्राधिकरण अर्ध न्यायिक तरीके से कार्य करता है, उन्होंने मेसर्स रमन एंड रमन लिमिटेड बनाम मद्रास राज्य और अन्य का हवाला दिया है, (1) जिसमें पैरा 5 में लॉर्ड शिप्स ने टिप्पणी की है।

"परमिट जारी करने वाले न्यायाधिकरणों के समक्ष कार्यवाही का चरित्र अर्धन्यायिक है।"

उन्होंने 'श्री राम विलास सर्विस (पी) लिमिटेड बनाम सी. चन्द्रशेखरन और अन्य का भी हवाला दिया है, (2) जहां उनके आधिपत्य ने टिप्पणी की थी।

"रिट याचिकाओं पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय को इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत तथ्यात्मक प्रश्नों के निर्णय उपयुक्त प्राधिकारियों पर छोड़ दिए गए हैं, जिन्हें इस संबंध में अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों में गठित किया गया है, और

इसलिए, तथ्य के सभी प्रश्नों पर उनके द्वारा दिए गए निर्णयों में कला 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त विशेष क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उस संबंध में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त परीक्षण संतुष्ट न हों। यह दिखाने के लिए कि अर्ध न्यायिक प्रकृति के आदेश की समीक्षा तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि संबंधित अधिनियम के तहत ऐसी शक्ति नहीं दी जाती है, उन्होंने दीप चंद और अन्य बनाम अतिरिक्त निदेशक, होल्डिंग्स समेकन, (3) का हवाला दिया है। जहां इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा यह टिप्पणी की गई।

“मेरी राय में, यहां सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले का उल्लेख करना लाभदायक है श्रीमती। वी. जी. पीटरसन बनाम ओ. वी. फोर्ब्स आदि और निम्नलिखित शिक्षाप्रद टिप्पणियों को पुन: प्रस्तुत करें: -

"हालांकि, जब हम पाते हैं कि न्यायालय ने संपत्ति को जब्त करने में अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया है और किसी भी मामले में, ऐसी संपत्ति को सरकार को सौंपने का आदेश देते समय हमें दूसरे महान सिद्धांत को याद रखना होगा जो कई साल पहले कहा गया था केर्न्स, एलसी के ये शब्द आर.ओजर बनाम कॉम्पटोइर डी. एस्कोम्पल डी पैन्स में, पृष्ठ 4715 पर। सभी अदालतों के पहले और सर्वोच्च कर्तव्यों में से एक यह ध्यान रखना है कि अदालत के अधिनियम से किसी भी दावेदार को कोई चोट न पहुंचे। यह कहने का मतलब, हम जानते हैं, यह नहीं है कि जब भी किसी न्यायालय को दो पक्षों के बीच किसी मामले में गलत निर्णय लेने के बाद पता चलता है कि निर्णय गलत था तो उसके पास मामले को फिर से खोलने और निर्णय को बदलकर मामले को सही करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है। . कई मामलों में जब न्यायालय ने कोई गलती की है तो उस गलती के लिए पीड़ित पक्ष के पास अपील, पुनरीक्षण या समीक्षा के प्रावधानों के अनुसार जो कुछ भी मिल सकता है उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, जैसा कि न्यायालय बार-बार इंगित करने में सावधानी बरतते हैं। कानून की अदालतों के पास गलत के साथ-साथ सही निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है और केवल तथ्य (कि निर्णय गलत है) किसी पक्ष को कोई उपाय नहीं देता है। मेरी राय में, ये टिप्पणियाँ न्यायिक क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र की किसी भी अंतर्निहित शक्ति को स्पष्ट रूप से नकारात्मक करती हैं। , और यदि मैं अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण के संबंध में भी ऐसा कह सकता हूं, तो एक निर्णय किए गए कारण को फिर से खोलना और केवल गुण-दोष के आधार पर इसमें त्रुटि पाए जाने पर निर्णय को बदलकर मामलों को सही करना।

मेरी राय में, समीक्षा की इतनी व्यापक शक्ति को स्वीकार करने से न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निर्णयों में स्थायी अनिश्चितता और अप्रत्याशितता के परेशान करने वाले तत्व आएंगे, जो अर्ध न्यायिक अराजकता का आभास देंगे, जिसे बनाए रखने के लिए मैं खुद को राजी नहीं कर सकता। यदि न्यायालयों के पास इतनी व्यापक और व्यापक शक्ति नहीं है तो वैधानिक न्यायिक या अर्ध-न्यायिक (न्यायाधिकरणों) में इतनी व्यापक शक्ति को स्वीकार करना मुश्किल है। हरभजन सिंह बनाम करम सिंह और अन्य में, (4) उनके आधिपत्य पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 से निपट रहे थे।

उस मामले में निर्धारण का प्रश्न यह था कि क्या होल्डिंग्स समेकन निदेशक के पास अपने पिछले आदेश की समीक्षा करने की शक्ति थी। उनके आधिपत्य ने टिप्पणी की:-

“एओटी में अधिनियम XXX की धारा 42 के तहत दिए गए आदेश के संबंध में राज्य सरकार को समीक्षा की स्पष्ट शक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: यह इस प्रकार है, निदेशक का 29 अगस्त, 1948 का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर और क्षेत्राधिकार के बिना है और उच्च न्यायालय ने संविधान की धारा 226 के तहत रिट जारी करके उस आदेश को रद्द करना सही था।'' वर्तमान मामले में यह विवादित नहीं है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्य परिवहन आयुक्त या समान प्राधिकरण को अर्ध-न्यायिक निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार दे सके।

(11) विद्वान महाधिवक्ता ने शिह प्रसाद मोन दाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (5) का हवाला दिया है, जिसमें यह टिप्पणी की गई थी।

'मेरी राय में न्यायिक कार्यवाहियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना अनावश्यक है। आर.टी.ए. ऐसे कर्तव्यों का पालन करता है जो प्रशासनिक होते हैं लेकिन अर्ध-न्यायिक प्रकृति के कुछ पहलुओं में होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों, जब उसे पता चलता है कि कोई आदेश अनजाने में इस बात को नज़रअंदाज करते हुए बनाया गया है कि इस बीच कानून बदल दिया गया है, तो उस आदेश को सुधारा नहीं जा सकता है। वह सब आर.टी.ए. ऐसा करने का तात्पर्य एक बड़ी गलती को सुधारना था जो कार्यवाही के दौरान सामने आ गई। इसे विशुद्ध न्यायिक कार्यवाही में समीक्षा के समान सख्ती और औपचारिकता के साथ नहीं माना जाना चाहिए। मुझे सोचना चाहिए कि कभी-कभी अर्ध-न्यायिक कार्य करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए ऐसी गलतियों को सुधारने की एक निहित शक्ति होती है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि 10 अप्रैल, 1958 का आदेश दोषपूर्ण है।”

विद्वान महाधिवक्ता का यह मामला नहीं है कि वर्तमान मामले में राज्य परिवहन आयुक्त ने वर्तमान याचिकाकर्ता को परमिट देते समय कोई गलती की है। यदि कोई परमिट प्राप्त किया गया है और राज्य परिवहन आयुक्त आईबी को रद्द या निलंबित करना चाहता है तो उसे अधिनियम की धारा 60 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

(12) विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 'उन्होंने राज्य परिवहन आयुक्त ने याचिकाकर्ताओं को दिए गए परमिट रद्द नहीं किए हैं और केवल पिछले आदेश को इस हद तक वापस ले लिया है कि उन्हें पुनर्विचार के लिए परमिट जमा करने के लिए कहा गया है। हमारा भी यही मानना है कि 'वह राज्य परिवहन आयुक्त हैं।' राधा राम बनाम नगर पालिका, बरनाला

(एस.एस. संधावालिया, सी.जे.)

पिछला आदेश याद नहीं आ रहा. इस संबंध में, दीप चंद और अन्य बनाम अतिरिक्त निदेशक, कंसोल डेटेशन ऑफ होल्डिंग्स (सुप्रा) का संदर्भ लिया जा सकता है जहां यह टिप्पणी की गई थी,

"यह तर्क कि किसी ग़लत आदेश को वापस लेने की शक्ति समीक्षा की शक्ति से अलग और अलग है और इसलिए, हर अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण में निहित है, समर्थित है न तो स्थिति के आधार पर और न ही किसी मान्यता प्राप्त सिद्धांत या मिसाल के आधार पर, और वास्तव में यह अंतर एक ठोस तर्क का आधार बनाने के लिए बहुत कमजोर प्रतीत होता है। क़ानून, प्रेरक सिद्धांत या बाध्यकारी अधिकार के अभाव में, जैसा कि वर्तमान में मुझे सलाह दी गई है, मैं गंजे विवाद को बनाए रखने के लिए खुद को मनाने में असमर्थ हूं, क्योंकि, मेरे विचार से, हमारे सामने वाले आदेश को वापस लेने की शक्ति केवल का दूसरा नाम है समीक्षा करने की शक्ति यदि, 'और इसलिए, सुझाव के अनुसार एक अलग और विशिष्ट क्षेत्राधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।' इसलिए, राज्य सरकार या राज्य परिवहन आयुक्त को पिछले आदेश को वापस लेने का भी अधिकार नहीं है।

(13) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम वर्तमान याचिका को स्वीकार करते हैं और आदेश अनुलग्नक पी. 2 और आर.आई. को रद्द करते हैं। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:

Deepak yadav

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy

Chandigarh